

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Thursday, 14 Nov , 2024

Edition: International Table of Contents

| | |
|---|--|
| Page 01 Syllabus : प्रारंभिक परीक्षा तथ्य | सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर संस्कृति' पर रोक लगाई |
| Page 07 Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था - कृषि | भारत के चाय, चीनी निर्यात ने घरेलू स्तर पर स्थिरता संबंधी चिंताएँ बढ़ाईं |
| Page 07 Syllabus : प्रारंभिक परीक्षा तथ्य | अफ्रीकी हाथियों की संख्या में कमी की चिंताजनक दर |
| Page 14 Syllabus : प्रारंभिक परीक्षा तथ्य | COP29 में 'अनवील्डी' प्रथम ड्राफ्ट ने 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया |
| समाचार में | बुकर पुरस्कार |
| Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति और सामाजिक न्याय | स्तरित भेदभाव का बेहतरीन मिश्रण |

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य द्वारा आरोपी व्यक्तियों को निशाना बनाकर की गई तोड़फोड़ के मामले में हस्तक्षेप किया, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जहां परिवारों को उचित प्रक्रिया के बिना दंडित किया गया।

- ➔ न्यायालय ने जवाबदेही सुनिश्चित करने और सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमानी कार्रवाई को रोकने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किए। इसने आरोपी और उनके परिवारों के संवैधानिक अधिकारों पर जोर दिया।

Supreme Court puts brakes on 'bulldozer culture'

Bench says States indulging in naked display of 'might is right' without thinking about victims

Court issues a series of 'binding directives' that include 15 days' prior notice to occupants

Destroying homes, leaving families homeless nothing short of 'anarchy', says Justice Gai

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Wednesday said the States that metamorphose into judges to punish accused persons awaiting trial by driving bulldozers into their homes, indulge in a naked display of "might is right" without sparing a thought for families rendered shelterless and destitute overnight.

A Bench of Justices B.R. Gavai and K.V. Viswanathan, in its verdict, invoked extraordinary powers under Article 142 of the Constitution to issue a slew of "binding directives" to fasten accountability on public officials.

They include 15 days' prior notice of demolition to the occupants; the notice must provide details of the nature of the unauthorised construction, specific violations and grounds warranting demolition; the owner or occupants who

want to challenge the State action must be given a fair opportunity by the designated authority; the final order of the authority must have reasoned conclusions; the actual demolition must be video-graphed, etc.

Officials will face action Officials who violate these directives would face contempt action and would be prosecuted. They would be liable for the restitution of the demolished property, the court said.

The 95-page judgment followed petitions representing citizens from several States, including Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan, who had sought redress against the States' "bulldozer culture". The petitioners had complained that their properties were demolished by the State machinery without due process of law on the ground that they were accused of criminal offences. The petitions



Wheels of injustice: Workers razing the property of an accused in an RSS attack case in Jaipur in October, citing violations. PTI

even claimed the demolitions had a communal tone.

On September 17, the top court *suo motu* extended the ambit of the case and barred such demolitions across the country.

"The chilling sight of a bulldozer demolishing a building, when authorities have failed to follow the basic principles of natural justice and have acted without adhering to the principle of due process,

reminds one of a lawless state of affairs, where might was right," the Bench said.

'Collective punishment' Justice Gai said the government could not transform itself into a judge to find an accused guilty without trial and deliver a "collective punishment" to him and his family by wrecking their home and their shared memories with a bulldozer. This

Jamiat hails verdict; victims 'disappointed'

NEW DELHI

Though the main petitioner, the Jamiat Ulama-i-Hind, termed the Supreme Court judgment against bulldozer demolitions "a historic verdict" which "set a template for the future", some of the victims expressed disappointment and demanded compensation. » PAGE 4

would be a violation of the 'rule of law', which was a part of the Basic Structure of the Constitution.

The judge said destroying family homes, leaving entire families homeless, was nothing short of "anarchy".

The executive actions of public officials must be consistent with maintaining public trust. "The greater the power to decide, the higher is the responsibility to be just and fair,"

Justice Gai observed.

"If his spouse, children, parents live in the same house or co-own the same property, can they be penalised by demolishing the property without them even being involved in any crime? As is well known, a pious father may have a recalcitrant son and vice versa. Depriving innocent people of their right to life by removing shelter from their heads, in our considered view, would be wholly unconstitutional," Justice Gai underscored.

An accused is presumed innocent until proven guilty in a court of law, the court reminded the States.

The principle of 'separation of powers' gave the courts, not the State, the authority to decide if a person was guilty of a crime or not. The State cannot take excessive measures even against convicts. There should be institutional accountability if public officials violate the rights of an accused or a convict

through arbitrary exercise of power, the court held.

The judgment said the burden was on the authorities to disprove in court the presumption that they did not demolish a structure to penalise the accused owner or occupant.

"When a particular structure is chosen all of a sudden for demolition and the rest of the similarly situated structures in the same vicinity are not even touched, mala fide may loom large," Justice Gai observed.

The court said for an average citizen, the construction of a house was often the culmination of years of hard work. "A house is not just a property but embodies the collective hopes of a family or individuals for stability, security, and a future... It gives a sense of dignity and a sense of belonging. If this is to be taken away, then the authority must be satisfied that this is the only option available," Justice Gai noted.

"बुलडोजर संस्कृति" पर संदर्भ और चिंताएँ

- ➔ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य द्वारा की गई तोड़फोड़ के मुद्दे को संबोधित किया, जिसमें मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे अभियुक्तों के घरों को निशाना बनाया गया, विशेष रूप से उन उदाहरणों की आलोचना की, जहाँ बिना उचित प्रक्रिया के तोड़फोड़ की गई।
- ➔ यह निर्णय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की याचिकाओं के बाद आया, जहाँ प्रभावित नागरिकों ने आरोप लगाया कि अभियुक्तों को दंडित करने के लिए तोड़फोड़ की गई, अक्सर सांप्रदायिक भावना के साथ।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश

- ➔ न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, तोड़फोड़ में शामिल राज्य अधिकारियों के लिए सख्त, बाध्यकारी निर्देश दिए।
- ➔ मुख्य निर्देशों में अनधिकृत निर्माण उल्लंघन और तोड़फोड़ के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए, रहने वालों को 15 दिन पहले अनिवार्य रूप से नोटिस देना शामिल है।
- ➔ रहने वालों को नामित प्राधिकारी के माध्यम से तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और किसी भी अंतिम निर्णय के साथ विस्तृत तर्क होना चाहिए।

- पूरी तोड़फोड़ प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए, और इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा और अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना

- सरकारी अधिकारी जो इन दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, अवमानना कार्रवाई, अभियोजन और नष्ट की गई संपत्ति की संभावित प्रतिपूर्ति का सामना करना पड़ेगा।
- न्यायालय ने कार्यकारी कार्यों में जनता के विश्वास के महत्व पर जोर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि उच्च शक्ति निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए अधिक जिम्मेदारी का आदेश देती है।

कानून का शासन और अभियुक्त के अधिकार

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि दोषी साबित होने तक अभियुक्त निर्दोष होता है, शक्तियों के पृथक्करण पर जोर देते हुए, जहाँ केवल न्यायपालिका को ही दोषी ठहराने का अधिकार है।
- सामूहिक दंड, जैसे अभियुक्त को दंडित करने के लिए परिवार के घरों को ध्वस्त करना, असंवैधानिक और "कानून के शासन" के विरुद्ध माना गया, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।

निर्दोष की रक्षा करना और जवाबदेही बनाए रखना

- न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के साथ रहने वाले निर्दोष परिवार के सदस्यों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, कथित अपराधों में शामिल न होने वाले परिवारों को दंडित करने की निष्पक्षता पर सवाल उठाया।
- अधिकारियों को अदालत में यह साबित करना होगा कि विध्वंस अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक उपाय नहीं था; चुनिंदा विध्वंस शक्ति के संभावित दुरुपयोग का संकेत दे सकते हैं।

घर और गरिमा का महत्व

- कई लोगों के लिए, घर बनाना वर्षों की कड़ी मेहनत और गरिमा और सुरक्षा का स्रोत होता है।
- कोर्ट ने कहा कि घरों को ध्वस्त करना केवल गहन मूल्यांकन के बाद ही अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, जो पारिवारिक घरों की पवित्रता और व्यक्तिगत महत्व को रेखांकित करता है।

Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत स्थापित संघीय अपील न्यायालय से छोटा है।
2. सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान स्वीकृत संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान करना होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है/हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) केवल 2

उत्तर: c)

भारत के कृषि निर्यात में तेज़ी से हो रही वृद्धि, जिसका मूल्य 2022-23 में 53.1 बिलियन डॉलर होगा, स्थिरता के बारे में चिंताएँ बढ़ाती है।

- चाय और चीनी जैसी उच्च मांग वाली वस्तुओं का उत्पादन पारिस्थितिक और सामाजिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जबकि बाज़ार जैसी वैकल्पिक फ़सलें टिकाऊ समाधान प्रदान करती हैं।
- भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

India's tea, sugar exports raise sustainability concerns at home

Agricultural commodity production in India lives in a unique context – high domestic consumption and now rapidly growing exports – that may benefit producers and consumers, but increasing dependencies between different parts of the supply chain compromise ecological sustainability

Dasari Giridhar
Manan Bhan

India is one of the world's largest agricultural product exporters. Indian agricultural export was valued at \$53.1 billion in 2022-23, up from \$8.7 billion in 2004-05, a six-fold increase in less than two decades. For an economically developing economy like India, exports play a significant role in strengthening the economy by increasing revenue, foreign exchange, and transactional options. But the rapid surge in exports poses multiple challenges to sustainability of the production, processing, and distribution systems of the respective commodities.

In this context, it's important to answer two questions regarding the sustainability of an agricultural commodity.

First, when can an agricultural commodity be considered truly sustainable? The sustainability of such a commodity isn't just about economic sustainability, which is driven by productivity. Ecological and social factors, aided by good governance, help build a sustainable production system, so the sustainability of an agricultural system depends on three pillars: ecological factors, economic aspects, and social aspects, underpinned by robust policies underlying all of them.

Second, should sustainability considerations only apply to production? No. Since the lifecycle of a commodity extends across pre-sowing, on-farm production, and post-harvest stages, sustainability applies to them all. Tea and sugar, two prominent commodities in India with a large domestic and export-oriented consumption base, offer good examples to illustrate the problems herein.

Tea
India is the world's fourth-largest tea exporter and second-largest producer, contributing 10% of global exports. The latter totalled 188.76 million kg in 2022, with a value of \$641.34 million, and an increase of 21.47% year on year in volume and 12.43% year on year in value. The total value of Indian tea exports for 2022-23 was \$733.78 million. Domestic consumption constitutes 80% of total production. The top export destinations of Indian tea are the United Arab Emirates, Russia, Iran, the U.S. and the U.K.

There is also growing evidence of stresses being imposed on production systems across the tea value chain. Three major challenges in the tea industry are the management of human-wildlife interactions, burgeoning chemical use, and labour concerns. An estimated 70% of tea plantations are situated at the periphery of forests and host the migratory routes elephants need to move around, resulting in frequent interactions with humans and human property and damage.

Likewise, synthetic pesticides constitute up to 85% of total pesticide use in tea plantations. This degree of reliance on such pesticides increases the chemical residue in the final product. Researchers have already documented an increase in the incidence of DDT, Endosulfan 35 EC, Dicofof 18.5 EC, and Cypermethrin 10 EC in tea. Exposure to these substances can increase the risk of cancer, diabetes, impaired neurodevelopment in children, and neurotoxicity.



Sweet and sour: Workers harvest sugar cane in Kolhapur district in Maharashtra. FILE PHOTO

Finally, the labour rights and working conditions of the tea estates cannot be undermined. More than half of tea plantation workers are women and they are often underpaid. The working conditions are also hazardous and workers often lack protective gear. Despite regulations under the Plantations Labour Act 1951 (amended in 2010 to strengthen worker safety), safety standards are almost never fully enforced. There is a critical need for better management practices in and around tea estates in India, stricter monitoring of the maximum residue limits for pesticides, and better enforcement of existing labour regulations.

Sugar
India is the world's second-largest sugar producer, with 34 million metric tonnes of production, which is about a fifth of the global production. India's sugar exports grew by 291% from \$1,177 million in FY 2013-14 to \$4,600 million in FY 2021-22 and 64.90% in 2022-23. The country exported sugar to 121 countries, according to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics. About 50 million farmers depend on sugar cane cultivation in India. An additional half million depend on sugar and allied factories. According to NITI Aayog, the industry has an annual turnover of ₹1 lakh crore.

But for the exports' economic value and the industry's significant rural employment, it also has considerable adverse environmental effects – but in particular water resource management.

Sugar cane is well-known for requiring a lot of water to cultivate. On average, 1 kg of sugar requires between 1,500 and 2,000 kg of water. Sugar cane and paddy occupy around 25% of the gross cropped area in India and consume 60% of the country's total irrigation water, reducing the availability for other crops and also stressing groundwater resources. In the

There needs to be more focus on addressing environmental issues and safeguarding the health and safety, of both workers and consumers, to develop an inclusive agrarian economy that benefits both local communities and global markets

last six or seven years, the area under sugar cane cultivation has almost doubled in Karnataka and Maharashtra.

Natural ecosystems like grasslands and savannahs in these states have also been converted to plant sugar cane. Along with the ensuing biodiversity loss, this change has increased the pressure on water resources and increased the need for sustainable water use and alternate cropping patterns. In fact, implementing drip irrigation in these states could lower water consumption by 40-50%.

The social dynamics of sugar industries narrate another story. Media reports have unearthed poor working conditions, including long working hours.

Rising temperatures in peninsular India acts as a threat multiplier, increasing the risks to workers' physical and mental well-being. Workers trapped in vicious debt cycles incur even more stress. Strengthening regulations and encouraging structured and responsible production practices are important to reduce these effects and promote sustainability.

Millets
Even as the sustainability challenges of these commodities persist, there are others that promote long-term ecological and socio-economic sustainability, and their successes could serve as templates to address the problems plaguing tea and sugar.

One prime example is millets, a sustainable option with which to increase

domestic consumption as well as exports. Millets are resilient to harsh conditions and don't require more inputs to weather resource constraints. They preserve soil health and ensure nutritional security.

The growing importance of millet export is evident in the export statistics. India reached a major milestone in 2021-22 when it exported millets valued at \$62.95 million, up from \$26.97 million in 2020-21, almost a 2.5-fold increase in a single year. In FY 2022-23, the country shipped 169,049.11 metric tonnes of millets and millet-related products worth \$75.45 million. This rising demand highlights their potential as a sustainable agricultural commodity contributing to economic growth and environmental resilience.

Agricultural commodity production in India lives in a unique context: a large domestic consumption base and now a rapidly growing export base. These dynamics may benefit producers and consumers but they could also yield a paradox: whereby increasing dependencies between different actors in the supply chain compromise ecological and social sustainability concerns. There are successful tales of increasing production and trade volumes but concerns also continue regarding the trickling down of some of those economic benefits to producers and farm labourers, and regarding the vitality of India's natural resources.

There needs to be more focus on addressing environmental issues and safeguarding the health and safety of both workers and consumers to develop an inclusive agrarian economy that benefits both local communities and global markets.

Dasari Giridhar is a research associate (giridharaditya24@gmail.com) and Manan Bhan is a Fellow in Residence (manan.bhan@atree.org) – both at the Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), Bengaluru.

परिचय

- ▶ भारत का कृषि निर्यात 2022-23 में 53.1 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो 2004-05 से छह गुना वृद्धि दर्शाता है, जो राजस्व और विदेशी मुद्रा के लिए निर्यात के आर्थिक महत्व को दर्शाता है।
- ▶ हालांकि, निर्यात की तेज़ वृद्धि, उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण प्रणालियों की स्थिरता के बारे में चिंताएँ पैदा करती है।

कृषि वस्तुओं के लिए स्थिरता को परिभाषित करना

- ▶ वास्तविक स्थिरता: एक कृषि वस्तु तब टिकाऊ होती है जब वह मजबूत शासन द्वारा समर्थित आर्थिक, पारिस्थितिक और सामाजिक मानदंडों को पूरा करती है।
- ▶ उत्पादन से परे: स्थिरता में बुवाई से पहले, खेत पर और कटाई के बाद के चरण शामिल होने चाहिए, जैसा कि चाय और चीनी उद्योगों में देखा जाता है।

चाय उद्योग में संधारणीयता संबंधी चुनौतियाँ

- ▶ वैश्विक स्थिति: भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चाय निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके प्रमुख निर्यात बाज़ार संयुक्त अरब अमीरात, रूस और यू.एस. हैं।
- ▶ मानव-वन्यजीव संघर्ष: लगभग 70% चाय बागान जंगलों की सीमा पर हैं, जिसके कारण वन्यजीवों, विशेष रूप से हाथियों के साथ अक्सर संपर्क होता है, जिससे संघर्ष होता है।
- ▶ रासायनिक उपयोग: चाय में पाए जाने वाले डीडीटी और एंडोसल्फ़न जैसे अवशेषों के साथ सिंथेटिक कीटनाशकों पर भारी निर्भरता उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है।
- ▶ श्रम संबंधी मुद्दे: बागान श्रम अधिनियम, 1951 जैसे नियमों के बावजूद श्रमिक, मुख्य रूप से महिलाएँ, अक्सर कम वेतन, असुरक्षित परिस्थितियों और अपर्याप्त सुरक्षात्मक गियर का सामना करती हैं।

चीनी उद्योग में संधारणीयता संबंधी मुद्दे

- ▶ उत्पादन पैमाना: भारत दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, जो 121 से अधिक देशों को निर्यात करता है; 2013-14 से 2021-22 तक चीनी निर्यात में 291% की वृद्धि हुई।
- ▶ पानी की खपत: गन्ना, एक जल-गहन फसल है, जो प्रति किलोग्राम चीनी में 1,500-2,000 किलोग्राम पानी का उपयोग करती है, जिससे अन्य फसलों के लिए संसाधन कम हो रहे हैं और भूजल पर दबाव पड़ रहा है।
- ▶ जैव विविधता प्रभाव: कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती के विस्तार ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है, जिससे जैव विविधता का नुकसान हो रहा है।
- ▶ श्रम संबंधी चिंताएँ: लंबे समय तक काम करने, कठोर परिस्थितियाँ और बढ़ते तापमान से श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याएँ और ऋण तनाव बढ़ रहे हैं, जिसके लिए सख्त नियमन की आवश्यकता है।

बाजरा: एक टिकाऊ विकल्प

- ▶ पर्यावरणीय लाभ: बाजरा सूखा प्रतिरोधी है, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो टिकाऊ कृषि का एक उदाहरण है।
- ▶ निर्यात वृद्धि: बाजरा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2022-23 में \$75.45 मिलियन तक पहुँच गया, जो आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए उनकी क्षमता को दर्शाता है।

निष्कर्ष

- ▶ भारत की कृषि दोहरे घरेलू और निर्यात बाजार के भीतर संचालित होती है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में पारिस्थितिक और सामाजिक स्थिरता संबंधी चिंताएँ बढ़ती हैं।
- ▶ अनुशांसा: पर्यावरणीय चुनौतियों, श्रमिक कल्याण और उपभोक्ता सुरक्षा का समाधान एक समावेशी और टिकाऊ कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे स्थानीय और वैश्विक दोनों बाजारों को लाभ होगा।

Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 के अंतर्गत शामिल है?

1. तिलहन
2. मिट्टी का तेल
3. उर्वरक
4. दालें

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 1 और 4
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 2 और 3
- d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: d)

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में अफ्रीकी हाथियों की आबादी में भारी गिरावट को उजागर किया गया है, जिसमें सवाना और वन हाथियों को अवैध शिकार और आवास के नुकसान से महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

- ▶ जबकि उत्तरी क्षेत्रों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, दक्षिणी अफ्रीका में संरक्षण प्रयासों से कुछ जनसंख्या में सुधार दिखाई देता है।

समाचार का विश्लेषण:

- ▶ एक व्यापक अध्ययन ने पिछले 50 वर्षों में अफ्रीकी हाथियों की आबादी में तेज गिरावट का खुलासा किया है, जो सवाना और वन हाथियों पर केंद्रित है।
- ▶ 37 अफ्रीकी देशों में 475 साइटों से डेटा का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि सर्वेक्षण किए गए स्थलों पर सवाना हाथियों की आबादी में लगभग 70% और वन हाथियों की आबादी में लगभग 90% की गिरावट आई है।
- ▶ औसतन, इन साइटों पर हाथियों की कुल आबादी में 77% की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण अवैध शिकार और आवास का नुकसान है।
- ▶ कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय विलुप्तियाँ देखी गई हैं, जिनमें साहेल जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक दबाव है।
- ▶ हालाँकि, दक्षिणी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों, जैसे बोत्सवाना, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में प्रभावी संरक्षण प्रयासों और सक्रिय प्रबंधन के कारण जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है।
- ▶ अध्ययन में कुल जनसंख्या की गणना नहीं की गई, लेकिन सर्वेक्षण किए गए स्थानों पर रुझानों का अवलोकन किया गया, पिछले अनुमानों के अनुसार 2016 तक संयुक्त जनसंख्या 415,000 और 540,000 हाथियों के बीच थी।

अफ्रीकी हाथी

- ▶ वैज्ञानिक नाम: लोकसोडोंटा अफ्रिकाना (सवाना हाथी) और लोकसोडोंटा साइक्लोटिस (वन हाथी)
- ▶ निवास स्थान: उप-सहारा अफ्रीका में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में पाया जाता है, जिसमें सवाना, जंगल, रेगिस्तान और दलदल शामिल हैं।
- ▶ भौतिक विशेषताएँ: सबसे बड़े भूमि जानवर; सवाना हाथियों के कान बड़े होते हैं और वे वन हाथियों से बड़े होते हैं।
- ▶ सामाजिक संरचना: मादा के नेतृत्व में मातृसत्तात्मक समूह, मजबूत पारिवारिक बंधन; नर अक्सर अकेले या अविवाहित समूहों में रहते हैं।
- ▶ आहार: शाकाहारी, प्रतिदिन 300 पाउंड तक वनस्पति खाते हैं।
- ▶ संरक्षण स्थिति: अफ्रीकी वन हाथी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, जबकि अफ्रीकी सवाना हाथी संकटग्रस्त है।
- ▶ संरक्षण प्रयास: अफ्रीकी हाथी कार्य योजना और
- ▶ CITES: परिशिष्ट I संरक्षण।



Shrinking species: An African elephant with her calves in northern Kenya. FILE PHOTO

Alarming rate of decrease in African elephant count

Reuters

African elephants, earth's largest land animals, are remarkable mammals that are very intelligent and highly social. They also are in peril. Fresh evidence of this comes in a study that documents alarming population declines at numerous sites across the African continent over about a half century.

Researchers unveiled on Monday what they called the most comprehensive assessment of the status of the two African elephant species – the savannah elephant and forest elephant – using data on population surveys conducted at 475 sites in 37 countries from 1964 through 2016.

Savannah elephant populations fell by about 70% on average at the surveyed sites and forest elephant populations dropped by about 90% on average at the surveyed sites, with poaching and habitat loss the main drivers. All told, there was a 77% population decrease on average at the various surveyed sites spanning both species. Elephants vanished at some sites while their populations increased in other places thanks to conservation efforts.

"A lot of the lost populations won't come back, and many low-density populations face continued pressures. We likely will lose more populations going forward," said George Wittemyer, a Colorado State University professor of wildlife conservation who helped lead the study published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences.

Savannah elephant populations fell by about 70% on average at the surveyed sites, and forest elephant populations dropped by about 90% on average at the surveyed sites

The forest elephant population is estimated to be about a third that of savannah elephants. Poaching has affected forest elephants disproportionately and has ravaged populations of both species in northern and eastern Africa.

"We have lost a number of elephant populations across many countries, but the northern Sahel region of Africa – for example in Mali, Chad, and Nigeria – has been particularly hard hit. High pressure and limited protection have culminated in populations being extirpated," Wittemyer said. But in southern Africa, elephant populations rose at 42% of the surveyed sites. "We have seen real success in a number of places across Africa, but particularly in southern Africa, with strong growth in populations in Botswana, Zimbabwe and Namibia. For populations showing positive trends, we have had active stewardship and management by the governments or outside groups that have taken on a management role," Wittemyer said.

The study did not track a continent-wide population tally because the surveys used different methods over different time frames to estimate local elephant population density. Instead, it assessed population trends at each of the surveyed sites. A population estimate by conservationists conducted separately from this study put the two species combined at between 415,000 and 540,000 elephants as of 2016, the last year of the study period. It remains the most recent comprehensive continent-wide estimate.

29वीं COP वार्ता विकासशील देशों को उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए एक नया जलवायु वित्त लक्ष्य (NCQG) निर्धारित करने पर केंद्रित है।

- ▶ प्रस्तावित विभिन्न वित्तपोषण विकल्पों के साथ, आम सहमति प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जो भाग लेने वाले देशों के बीच भिन्न प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

'Unwieldy' first draft at COP29 sets 2030 goal of \$5 trillion

Jacob Koshy
NEW DELHI

Two days into 29th edition of the Conference of Parties (COP), the first major negotiating text that will decide if the two-week-long conclave will be a success has come out. While this is far from any semblance of finality, it lists out the universe of options before 190 countries that they must collectively whittle down – every country's vote is exactly as important as the other – and adopt before the conference ends.

The most prominent feature of the text is an ask of at least \$5-6.8 trillion until 2030, as the so called New Collective Quantified Goal (NCQG) on Climate Finance, for developing countries to meet their Nationally Determined Contribution (NDC), or volun-

tary targets that are updated periodically, where countries specify targeted action undertaken to reduce carbon emissions and substitute fossil fuel energy sources with renewable energy ones.

While there are multiple technical issues being deliberated upon at Baku, the headline-moment that the hundreds of negotiators are working upon, is the NCQG.

This is an estimate of the money that developing countries will collectively require from developed countries to adapt to climate change and shift to renewable sources without compromising on developmental needs.

The existing estimate, agreed upon in 2009, was to mobilise and deliver \$100 billion annually from 2020-2025 but was fulfilled – not to universal agree-



Building consensus: Bangladesh's Muhammad Yunus, centre right, attends the COP29 summit in Baku on Wednesday. AP

ment – only in 2022.

As the text stands however, there are a plethora of options within the NCQG. Large parts of the text are divided into 'options'. Regarding the quantum of NCQG itself there are four options. At the end of two weeks, countries are expected to choose one.

The range of options ex-

tend from the blanket \$5-7 trillion until 2030; 5.0-6.8 trillion for the pre-2030 period, and a separate 'adaptation finance' of \$215-387 billion annually up until 2030; or another that estimates \$ 455-584 billion per year, with no year specified and an acknowledgment that were "significant gaps and limitations due to gaps in information on the

processes and approaches used in determining needs, the methodologies and underlying assumptions used, and a lack of available data, tools, capacities."

Then there are other clauses, with their own sub-options, that call upon developed countries to explicitly acknowledge that they have not met their prior commitment of delivering \$100 billion in 2020 and 2025 and that they commit to paying the arrears. (In the UN accounting system, such flows have only been accounted upto 2022). There are disputes on whether, as developed countries, claim that \$115 billion had been delivered as climate finance in 2022.

A member of India's negotiating team told *The Hindu* that currently countries had formed blocks, or

negotiating alliances, among themselves and demanded insertions of paragraphs that included everybody's demands.

"India has a joint position with China and other developing countries as of now. Groups have sent representations and we are still analysing the latest version of the text. There are some major omissions. The text is too big now and it is a long road ahead," the person said.

"Countries asked for a new text that reflects all their positions. The new text does this but, unsurprisingly, it's now much longer and unwieldy, taking us back to the length the text was earlier in the year. It will need to be streamlined again to be workable," Joe Thwaites, Senior Advocate, International Climate Finance, said in a statement.

समाचार का विश्लेषण:

- ▶ 29वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज (COP) ने एक प्रारंभिक वार्ता पाठ जारी किया है, जिसमें 190 देशों द्वारा जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं के लिए विकल्पों की रूपरेखा दी गई है।
- ▶ ध्यान में रखा जाने वाला मुख्य मुद्दा जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) है, जिसमें विकासशील देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक कम से कम \$5-6.8 ट्रिलियन का प्रस्ताव दिया गया है।
- ▶ यह निधि विकासशील देशों को उत्सर्जन को कम करके और नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण करके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्राप्त करने में सहायता करेगी।
- ▶ NCQG राशियों के लिए कई विकल्प पाठ में शामिल हैं, जो \$5-7 ट्रिलियन से लेकर अन्य संरचित वार्षिक अनुमानों तक हैं।
- ▶ खंडों में विकसित देशों से 2020-2025 के लिए निर्धारित पिछले \$100 बिलियन वार्षिक लक्ष्य से अधूरी प्रतिबद्धताओं को मान्यता देने का आह्वान किया गया है।
- ▶ संभव समझौतों तक पहुँचने के लिए दस्तावेज़ को दो सप्ताह की COP अवधि में सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी।

Mains Practice Question

प्रश्न: जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी) के 29वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन करें। इस सम्मेलन में भारत द्वारा क्या प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की गईं?

In News : Booker Prize

ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृष्ठभूमि पर आधारित लघु, आश्चर्य से भरपूर उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता।



बुकर पुरस्कार के बारे में:

- यह एकल कथा साहित्य के लिए दुनिया का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है।
- यू.के. में 1969 में स्थापित, बुकर पुरस्कार ने शुरू में राष्ट्रमंडल लेखकों को पुरस्कृत किया और अब यह दुनिया भर में फैल गया है: यह मूल रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है।
- इसका उद्देश्य वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को पुरस्कृत करके कथा साहित्य में सर्वश्रेष्ठ को बढ़ावा देना है।

पात्रता:

Daily News Analysis

- बुकर पुरस्कार किसी भी उपन्यास को पुरस्कृत करता है जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया हो और पुरस्कार के वर्ष में यू.के. और आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो, चाहे उनके लेखक की राष्ट्रियता कुछ भी हो।
- उपन्यास अंग्रेजी में एक मूल रचना होनी चाहिए (अनुवाद नहीं)।
- इसे पंजीकृत यू.के. या आयरिश छाप द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए; स्व-प्रकाशित उपन्यास पात्र नहीं हैं।
- विजेता को £50,000 मिलते हैं, और प्रत्येक शॉर्टलिस्ट किए गए लेखक को £2,500 दिए जाएंगे।
- बुकर पुरस्कार फाउंडेशन: यह 2002 में स्थापित एक पंजीकृत चैरिटी है। 2005 में अपने उद्घाटन के बाद से, यह फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के पुरस्कार के लिए जिम्मेदार है।



The perfect cocktail of layered discrimination

Delimitation, the biggest elephant in the room called the Indian Union, is about to take centre stage. Statesmen such as Indira Gandhi and Atal Bihari Vajpayee appreciated the explosive potential of delimitation and kicked the can down the road, as it were, to be handled by a future generation. Here we are as that future generation. Do we kick the can further down the road? Do we detonate it? Or do we defuse it? We, the people of India, are at a historical crossroad. Will India remain a federal union? Or will it become an ethno-linguistic majoritarian mega state with minority ethno-linguistic minorities?

Federalism is part of the inviolable basic structure of the Constitution of India. The Indian Union is a federal union. States are the federating units. Most States find their basis in language and many States of the Indian Union are continuations of ethno-linguistic homelands that have existed for centuries or even millennia. This is precisely why the Supreme Court of India has termed States as political units and not arbitrary administrative units.

Indian unity was forged in the anti-imperialist struggle against British imperialism and that unity continues in independent India through a delicate balance of power distribution between federating units and ongoing dialogue between diverse peoples of the Indian subcontinent.

What is delimitation? Article 82 of the Indian Constitution requires that the number of Lok Sabha seats per State is recalibrated after each Census by the Delimitation Commission, in accordance with the population. Delimitation last happened based on the 1971 census, when in 1976, the Indira Gandhi government suspended the delimitation process for 25 years, until 2001. It was further suspended for another 25 years by the A.B. Vajpayee government, and would lapse by 2026, unless another amendment is introduced. The freezing of delimitation was done in order not to disincentive States that were effective in population control. However, the Narendra Modi government has given hints about undertaking fresh delimitation before the elections in 2029.

Delimitation as a threat

Total Fertility Rate (TFR) is a demographic indicator that estimates the average number of children a woman gives birth to during her reproductive years. Even today, TFR of non-Hindi States such as Kerala, Tamil Nadu and West Bengal is in the 1.6-1.8 range, below the replacement level of 2.1. The TFR of Hindi heartland States such as Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh, at about 3.5, is well above the replacement level. This has been true for many decades and thus by now, a recalibration via delimitation will mean a radical decrease in the proportion of non-Hindi State seats in the Lok Sabha. For example, if



Salem Dharanidharan

a spokesperson of the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) party and the Deputy Secretary of the party's IT wing



Garga Chatterjee

General Secretary, Bangla Pokkho

Under the existing formulation of delimitation, there is a grave risk of some 'unsuccessful' States becoming the 'owners of an imperial centre', imperilling 'successful' States

delimitation takes place, the proportion of seats in Parliament for the southern States would be reduced from 25% to 17% and the number of seats from Hindi heartland States where the Bharatiya Janata Party (BJP) has electoral dominance would increase from 40% to 60%.

States such as Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu already receive only about 30% of the total funds that contribute as direct taxes, while Bihar and Uttar Pradesh receive between 250% and 350% of their overall contribution. The decision of 16th Finance Commission to include the 2011 Census instead of the 1971 Census to devolve funds to States will be even more discriminatory to developed States. It is cause for worry that continuation of the same pattern would profoundly exacerbate the already existing bias against the non-Hindi States.

Fostering discrimination

India was conceived as a permanent, multi-ethnic, multi-lingual federal union, not as a mono ethno-linguistic majoritarianism territory. The difference with states such as China and Russia is that they are only federal in name, the population being made of an ethno-linguistic group with a majority of upwards of 80% and several other small minority nationalities. In India's case, however, there never was a majority ethno-linguistic group. India is a federation of various ethno-linguistic stakeholders, none of whom is a majority in India. But the major ones among them form the basis of various linguistic States, where they are super majority. But with long-term differences of TFR among States, and thereby, ethno-linguistic groups, this long-settled pattern faces the threat of being unsettled. Since 1947, the population proportion of Bengali, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil and Telugu have all decreased while the population proportion of one language, Hindi, has massively increased, from 36% to nearly 43%; 43% is not too far away from the majority.

The ratio of Lok Sabha seats allocated to a State to the total number of Lok Sabha seats represents the Stakeholdership Index of a State in matters of the Union. Delimitation will reward the non-performers of population control policies that will effectively dominate and determine the policy of the Union. The performers will have a declining say and will be reduced to being mere revenue contributors. The proportion of GDP and revenue from non-Hindi States is much greater than their population percentage while the proportion of GDP and revenue from Hindi States is lesser than their population percentage.

Post delimitation, States such as Bihar and Madhya Pradesh, where the BJP is dominant, will have their Stakeholdership Index nearly double, whereas States such as Kerala and Tamil Nadu where the BJP has one to zero seats will see it being reduced by 30%-40%. Such a situation would skew Indian democracy in favour of the

Hindi States, with other regions risking a loss of electoral dominance. Without electoral dominance and representation in the Union, this would further alienate the non-Hindi states.

Thus, the implementation of delimitation will create the perfect cocktail of layered discrimination. Non-Hindi States that have implemented population control measures successfully will lose a say in Union affairs. Non-Hindi States that contribute a majority of GDP, resources, revenue and taxes will lose say in how their monies are used. The 'unsuccessful' will create policies for the 'successful' with money from the 'successful'. No taxation without representation was the cry in the Boston Tea Party. In a similar vein, delimitation will further shrink the representation of States that produce taxes. This is a very risky and dangerous path to pursue. There is no place for any system in India where some States increasingly look like owners of an imperial centre while others mimic colonies. Therefore, it is necessary to balance two competing constitutional values: formal equality in voting and federalism.

Possible solutions

There can be many solutions. First, just follow what Mrs Gandhi and A.B. Vajpayee did and extend the freeze by another 25 years and defer to a future generation.

Second, permanently freeze delimitation as far as the India-wide redistribution of seats across States is concerned.

Third, go through with delimitation as envisaged. But supplement it with a long-due new grand federal compact such that the Concurrent List is abolished in favour of an expanded State list, all residual powers vested to the States and large-scale transfer of subjects are made from the Union list to the State list, keeping external defence, external affairs and currency in Delhi's hands. This would balance delimitation with decentralisation, softening the majoritarian blow inherent in delimitation.

Fourth, preserve the present seat proportion between States in the Lok Sabha but increase the number of seats in each State to partially offset the representational deficit of population explosion States.

India is a unique experiment. It is not an ethnic-linguistic majoritarian empire like Russia or China. It is not a mono-linguistic nation state such as Bangladesh and Thailand. India is like Africa or Europe, a tapestry of languages, ethnicities, cultures, civilisations and faiths, but with a crucial difference. It is bound in an inseparable political Union born in the crucible of anti-imperialist struggle with one, unified voice when speaking to others. India is the grandest experiment of plurality in modern human history. Majoritarianism and partisanship cannot be allowed to undo it and threaten its unity. History will not forgive us.

GS Paper 02 : भारतीय राजनीति एवं सामाजिक न्याय

UPSC Mains Practice Question: यदि परिसीमन को संघीय सिद्धांतों को संतुलित किए बिना लागू किया जाता है, तो इससे भारत में क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ सकती हैं। भारत के संघीय ढांचे पर परिसीमन के संभावित प्रभाव पर चर्चा करें और राज्यों में समान प्रतिनिधित्व बनाए रखने के उपाय सुझाएँ। (150 words/10m)

संदर्भ :

- ▶ भारत में परिसीमन का मुद्दा, जिसमें जनसंख्या के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना शामिल है, प्रमुखता प्राप्त कर रहा है।
- ▶ हिंदी भाषी और गैर-हिंदी भाषी राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय असमानताएँ बड़े राजनीतिक बदलावों को जन्म दे सकती हैं।
- ▶ इससे भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करने, क्षेत्रीय असमानताओं और अलगाव को बढ़ावा देने का खतरा है।

परिचय: परिसीमन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है

- ▶ परिसीमन, जनसंख्या के आधार पर प्रति राज्य लोकसभा सीटों की संख्या को फिर से निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है, जो भारत में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है।
- ▶ इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पिछले नेताओं ने इस मुद्दे को टाल दिया, क्योंकि इसकी विस्फोटक क्षमता को पहचाना गया था।
- ▶ वर्तमान पीढ़ी अब इस चुनौती का समाधान करने के बारे में एक चौराहे पर है।

संघवाद और भारत की राजनीतिक संरचना

- ▶ भारत एक संघीय संघ है, जिसमें राज्य मुख्य रूप से भाषा और जातीयता के आधार पर संघबद्ध इकाइयाँ हैं।
- ▶ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य मनमानी प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं बल्कि राजनीतिक संस्थाएँ हैं।
- ▶ भारतीय एकता ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में बनी थी, और यह राज्यों के बीच सत्ता के वितरण के संतुलन के माध्यम से जारी है।

परिसीमन क्या है?

- ▶ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, परिसीमन जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों की संख्या की पुनर्गणना करता है।
- ▶ यह प्रक्रिया पिछली बार 1971 की जनगणना के आधार पर आयोजित की गई थी।

- ▶ इंदिरा गांधी और वाजपेयी सरकारों ने 25-25 साल के लिए परिसीमन को निलंबित कर दिया था।
- ▶ यह रोक 2026 में समाप्त होगी, जब तक कि कोई नया संशोधन पारित नहीं हो जाता।
- ▶ केंद्र सरकार ने 2029 के चुनावों से पहले नए परिसीमन का संकेत दिया है।

परिसीमन का खतरा

- ▶ गैर-हिंदी राज्यों पर असंगत प्रभाव: केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, जिनकी प्रजनन दर कम है (1.6-1.8), संसद में उनके प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण कमी देख सकते हैं। इसके विपरीत, उच्च प्रजनन दर (लगभग 3.5) वाले हिंदी भाषी राज्यों में सीटों में वृद्धि देखी जा सकती है, जिससे हिंदी भाषी राज्यों का राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत होगा।
 - यदि परिसीमन होता है, तो दक्षिणी राज्यों की संसदीय सीटें 25% से घटकर 17% हो जाएंगी, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की हिस्सेदारी 40% से बढ़कर 60% हो जाएगी।
- ▶ भेदभावपूर्ण निधि आवंटन: महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य करों में अधिक योगदान करते हैं, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में उन्हें बदले में काफी कम मिलता है। 16वाँ वित्त आयोग इस असंतुलन को और बढ़ाता है।

बहुसंख्यकवाद और क्षेत्रीय अलगाव के जोखिम

- ▶ चीन या रूस जैसे देशों के विपरीत, भारत के जातीय-भाषाई समूहों की विविधता इसके संघवाद का केंद्र है।
- ▶ हालाँकि, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि हिंदी भाषी क्षेत्रों में केंद्रित होने के कारण, यह जोखिम है कि ये राज्य अधिक विकसित, गैर-हिंदी राज्यों की कीमत पर राष्ट्रीय नीति पर हावी हो सकते हैं।
- ▶ परिसीमन से संघ के मामलों में गैर-हिंदी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद और करों में असंगत हिस्सेदारी के बावजूद उनका प्रभाव कम हो सकता है।

प्रस्तावित समाधान

- ▶ फ्रीज को आगे बढ़ाएँ: पिछली सरकारों की तरह, परिसीमन पर रोक को अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ाएँ, ताकि यह मुद्दा भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया जाए।
- ▶ सीमन को स्थायी रूप से रोक दें: राज्यों में सीटों के भविष्य के पुनर्वितरण को रोकें।
- ▶ नए संघीय समझौते के साथ परिसीमन को लागू करें: परिसीमन के साथ आगे बढ़ें लेकिन साथ ही राज्यों को अधिक शक्तियाँ हस्तांतरित करके संघवाद का पुनर्गठन करें, खासकर वर्तमान में समवर्ती सूची के तहत मामलों पर।
- ▶ मौजूदा राज्यों में सीटें बढ़ाएँ: वर्तमान सीट आवंटन को बनाए रखें लेकिन कुछ राज्यों में जनसंख्या वृद्धि को संतुलित करने के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या बढ़ाएँ।

निष्कर्ष: संतुलन की आवश्यकता

- ▶ भारत का संघीय ढांचा किसी भी अन्य राष्ट्र-राज्य के विपरीत विविधता में एक अनूठा प्रयोग है।
- ▶ शक्ति के नाजुक संतुलन को बाधित करने से बचने और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए परिसीमन को सावधानी से संभाला जाना चाहिए।